

प्रेषक,

आलोक कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

देहरादून: दिनांक: 21 फरवरी, 2015

राजस्व अनुभाग-2

विषय-जौनसार बावर सेवावृत्त कर्मचारी मण्डल, देहरादून को ग्राम सुद्धोवाला परगना पछवादून, तहसील विकासनगर में जौनसारी भवन के निर्माण हेतु 0.1540 है० भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने हेतु एक मुश्त नजराने की धनराशि माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जौनसार बावर सेवावृत्त कर्मचारी मण्डल, देहरादून को ग्राम सुद्धोवाला परगना पछवादून, तहसील विकासनगर में जौनसारी भवन के निर्माण हेतु 0.1540 है० भूमि, शासनादेश संख्या-258/16(1)/73-रा०-1 दिनांक-09.05.1984 एवं संशोधित शासनादेश संख्या-1695/97-1-1(60)/93-280-रा०-1 दिनांक-12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए नजराने की धनराशि रु० 92,40,000/- (रु० बयानवे लाख चालीस हजार मात्र) को माफ करते हुए केवल नई दरो पर निकाली गई मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा, जिसके लिए वह स्वीकृत की गयी है।
2. प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान व संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
3. प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/01/85(24)-रा०-6 दिनांक-09.10.1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गर्वनमेन्ट ग्रांट एक्ट, 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के $1-1/2$ गुना से कम नहीं होगा।
4. प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

Alok

5. यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भागों से मुक्त निहित हो जायेगी।
6. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में गैर वानिकी कार्य हेतु भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
7. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-1 से 6 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया तत्क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश के शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

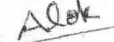
(आलोक कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-402 (1)/XVIII(II)/2015 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. अध्यक्ष, जौनसार बावर सेवावृत्त, कर्मचारी मण्डल, 101 तपोवन विहार, नालापानी रोड़, देहरादून।
- ✓ 4. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(आलोक कुमार सिंह)
अनु सचिव।